जरिए भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे ताकि रेलवे वैगनों के अभाव के कारण जो नियति बन्द हुआ है और जो 11 लाख टन और पडा हुआ है और उठाया नही जा रहा है, वह चालू हो सके।

REFERENCE TO STOPPAGE OF WORK ON THE FARAKKA FEEDER CANAL

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to draw the attention of the Minister of Irrigation and Power to a serious situation arising out of the stoppage of work on the Farakka Feeder Canal. The 'Ananda Bazar Patrika' of 8th May has expressed its grave concern over the total stoppage of work on the Farakka Feeder Canal. It has been stopped due to the non-participation of the engineers who were working on the project. Recently they have not been allowed by the Central Government to work. In the canal Rs. 4 crores worth of earth-moving work has been stopped. If the work on the canal is not completed before monsoon, 40,000 cusecs of water will not be guaranteed for the Hooghly river and both the ports of Haldia and Calcutta will be severely affected. I would urge upon the Government to allow the engineers to work on the feeder canal, so that the work can be completed before the monsoon breaks. Now, Sir, funds should also be given to the State Government of West Bengal so that the works could be completed before the monsoon. Otherwise the entire State of West Bengal will suffer and some parts of Bihar also will be affected by serious floods. I want to draw the attention of the Irrigation Minister and urge upon him to complete the work before the monsoon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 3.30 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at thirtytwo minutes past three of the clock, **The Vice-Chairman (Shri V. B. Raju)** in the Chair.

RESOLUTION *RE.* APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO SUGGEST REMEDIAL MEASURES TO CHECK, INFLUX OF RURAL POPULATION TO URBAN AREAS

—*contd.*

श्री देवराव शिवराम पाटिल (महाराष्ट्र) : उप-सभापति जी, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के भारी संख्या में आने के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका भाग 2 बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी और देहाती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विषमता के बारे में मैं चर्चा नही करना चाहता। यह जो संकल्प है इसके माध्यम से गरीब लोगों के लिए रोजगार और आय की व्यवस्था करने की मांग की गई है और मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे मै इस रेजलूशन बोलना कर चाहता हूं।

ग्रामों के लोग शहरो में जाते है उसके कई कारण होते हैं। पढ़े-लिखे लड़के अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, कोई इंडस्ट्री वहा बनी तो उसमें काम करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, उनकी चर्चा करना मैं वहां उचित नही समझता। लेकिन देहात के लोग जो अपने देहात मे तथा दूसरे देहात में जाने के बावजूद जिनको रोजी नही मिलती, रोजगार नही मिलता और इससे जो देहाती लोग शहरो मे जाते है यह एक बड़ी समस्या है और इसी समस्या पर मैं आपकी मार्फत इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

उप-सभापति जी यह समस्या बहुत जटिल है और इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। उन लोगों की चर्चा होती है जिनको रोजी की हमने गारन्टी दी है, सरकारी कर्मचारी हो

[श्री देवराव सिवराम पाटिल]

या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों उनको नौकरी पर लगने के बाद कम से कम 55 या 58 साल तक रोजी की गारन्टी दी जाती है। लेकिन देहात में एक ऐसा वर्ग है जो काम करता है, कष्ट करता है, लेकिन इस वर्ग को रोजगार की कोई गारन्टी नहीं दी है और उसकी संख्या कुछ कम नहीं है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूं कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, यानी हमारे प्लानिंग में 1972 में जो हमने 40 रुपये मुकरर्र किये थे उसके नीचे के जो लोग है, जिनकी कमाई 40 रुपये से कम होती है उनको उस पर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है।

एक महीने में 40 रुपये उन को नहीं मिलते हैं और उन लोगों की जो संख्या आज हमारे देश में है अगर उस को देखा जाय तो वह आप को लोक सभा के क्वेश्चन नं० 5623 डेटेड 3-4-74 से पता लगेगी। यह अप्रैल में ही पूछा गया क्वेश्चन है और उस में बताया गया है कि आल इंडिया लेबिल पर, स्टेट पापुलेशन बिलो पावर्टी लाइन, आल इंडिया मे रूरल एरियाज मे है 179793 और अरबन एरियाज में है 45832, यानी दोनों मिला कर दो करोड़ 25 लाख के ऊपर उन की तादाद है। यानी हमारे देश में दो करोड़ 25 लाख ऐसे लोगों की संख्या है कि जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं और वे लोग खास कर देहात मे रहते हैं। अरबन एरिया में जो उन की पापुलेशन दी गयी है उस की अगर इक्वायरी की जाय तो पता चलेगा कि शहर मे ऐसे लोगों के जो अकड़े यहां दिये गये हैं वे ज्यादातर देहात के ही रहने वाले हैं। आप बंबई या दिल्ली में जा कर पता करें, वहां झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वह देहातों से ही आ रहे हैं और उन की यह पापुलेशन है और इस लिए यह जो दो करोड 25 लाख बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं वे आज देश के सामने एक बड़ी समस्या हैं।

उप-सभापति महोदय, इस में दूसरा सवाल पर कैपिटा कंजंप्शन का दिया गया था। इस में राज्य सभा क्वेश्चन नं० 308, डेटेड 29 नवम्बर, 1973 में जो इंफर्मेशन दी गयी है कि :

Information about the *per capita* consumption expenditure is available only at the All-India level for the years 1952, 1960-61 and 1967-68.

1967-68 ....Rural Rs. 10.54 and Urban Rs. 12.95.

इस को देख कर किसी भी सदस्य को परेशानी हो जायगी कि रूरल एरिया में 10.54 और अरबन एरिया में 12.95 मैं इस बात का जिक्र इस लिए कर रहा हूं कि आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है। हम ने कितने ही प्रयत्न किये हैं। दूसरा एक सवाल मैं देना चाहता हूं। बंगाल में रीसेंटली एक सर्वे हुआ था और हमारे बंगाल के दोस्त यहां हैं इस लिए मैं बताना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि देहात मे जो लोग हैं उन की परिस्थिति बहुत सुधरी है। सौ प्रतिशत वहां के लोगों की आर्थिक परिस्थिति सुधरी है। यह सुधरी है या नहीं यह देखने की बात है। इस सवेक्षण में जो कहा गया है वह है कि .

"Standard of living worsens" This is what the Economic Times of Sunday, May 5, 1974 has to say :-

"The unmistakable and positive deterioration in the living standards of people in the rural areas despite developmental activities through Five-Year Plans was brought

out in a case study of two villages in West Bengal in 1960 and again in 1973 by the Agro-Economic Research Centre, Visva-bharati, Santiniketan.

"All the indicators, such as the level of enterprise, level of income and level of living showed that the villages were at a lower level in the later period than they were earlier. The level of living as reflected in the per capita per day consumption of cereals, per capita annual expenditure on certain items, housing and the use of durable consumer goods did not show any improvement over the period. In per capita terms there was a decline in income in both the villages. Agricultural labourers and those engaged in miscellaneous occupations and belonging to the lowest income categories had become poorer."

मंत्री महोदय ने एक दफा 'नवभारत टाइम्स' में 10 सितम्बर, 1973 में कहा है कि "विगत 25 वर्षों में जो भी विकास हुआ उसका फल समाज के केवल एक छोटे से अंग को मिला है। निर्धन और धनवान के बीच खाई ज्यादा चौड़ी हो गई है और पीड़ा और त्रास का दायरा भी बढ़ गया। भविष्य का सारा उत्पादन कार्यक्रम सर्वसाधारण की बुनियादी जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। समय आ गया है जब देश की गरीबी से मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाना ही चाहिए।" प्लानिंग मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी 29 अगस्त, 1972 के 'नवभारत टाइम्स' में कहा है कि "देश में योजना सफल नहीं रही जनतांत्रिक विकास में जनता के निचले वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्रामीण ईकाई कार्यक्रम पर योजना बनाई जानी चाहिए।"

मैंने यह सबूत इसलिए दिए ताकि पता लगे कि आज की देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है और देहात की परिस्थिति क्या है? बेरोजगारी के बारे में अगर देखा जाए तो यही हालत देहात के बारे में आपको नजर आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि खेती की पैदावार कुछ बढ़ी है और उससे खेतिहर मजदूर को कुछ रोजगार मिला। लेकिन हाल की जांच से ज्ञात हुआ है कि वर्तमान आर्थिक वर्ष में पंजाब राज्य में बेकारों की संख्या बढ़कर 4 लाख 18 हजार हो जाएगी। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। सुशिक्षित बेकारों की संख्या देहातों में भी बढ़ती जा रही है। शहर में जो सुशिक्षित लोग हैं उसकी संख्या तो दे दी जाती है लेकिन देहात में जो लोग हैं, जो मैट्रिक पास किए हुए हैं उन बेरोजगारों की संख्या का कुछ पता नहीं। जहां डिस्ट्रिक्ट में एम्पलाएमेन्ट एक्सचेंज होता है उसमें जो कोई नाम देता है उन्हीं के नाम उसमें होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया गया है। प्लानिंग कमीशन ने भी इतना कष्ट नहीं किया कि इस बारे में कोई स्पष्ट आंकड़े इकट्ठे कर सके। प्लानिंग कमिशन ने 66 पेज पर यह भी कहा है:

As pointed out in the Draft Fifth Five-Year Plan, since two-thirds of the population are engaged in agriculture, about the same proportion of additional labour force will be generated in this programme.

इतनी पापुलेशन होने के बावजूद भारत में कृषि उद्योग की स्थिति क्या है? सभापति महोदय, भारत में दलित जातियां हैं और उन्हीं के समान हमारे दलित उद्योग भी है जिसमें दुर्भाग्य से एक कृषि भी है। अभी तक कृषि को उद्योग नहीं माना गया है। एग्रीकल्चर इज नोट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री करके गावर्नमेंट ने इसको माना नहीं है। देश की 69 8 प्रतिशत आबादी का कृषि सहारा है। राष्ट्रीय आय में 47.5 प्रतिशत योगदान करना है। कृषि, निर्यात का भी एक प्रमुख साधन है। जनसंख्या के आधार पर यदि देखा जाए तो 70 प्रतिशत

[श्री देवराव सिवराम पाटिल]

पापुलेशन कृषि पर आधारित है। अगर उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो 50 परमैन्ट नैशनल इन्कम कृषि से आती है। इसके अनुसार कृषि विकास के लिए प्लानिंग कमिशन मे कोई प्राविजन नहीं है। इतना ही नही, अग्रिकलचर मिनिस्ट्री मे इसके बारे मे जो प्लान किया था उसको भी 700 करोड मे घटाने की कोशिश चल रही है। किसान की परिस्थिति अगर देखी जाए तो 40.7% प्रतिशत किसानों के पास 2.5 एकड़ की खेती है। मैं इसलिए आकड़े दे रहा हूं क्योंकि गलतफहमियां ऐसी हो गई हैं कि हिन्दुस्तान में बडे बड़े काश्तकार हैं। भारत में 6.296 प्रतिशत किसान परिवारों के पास 5 एकड़ जोत से कम भूमि है जो कुल कृषि योग्य भूमि का 18.88 प्रति शत बना। यह छोटे किसानों की उपेक्षा भारत की उपेक्षा होगी। भारत की जनसंख्या का लगभग 44 प्रतिशत भाग इसी 18.88 प्रतिशत भूमि पर आश्रित है। इसलिए अच्छी से अच्छी कृषि की योजनाएं बनाए बिना उनका सवाल हल नहीं होता है। आज देहात की परिस्थिति यह बन रही है कि जो छोटे क्रिसान हैं वे श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए वाध्य हो रहे हैं और दूसरे के ऊपर आश्रित होने लग गए है। छोटे और बड़े किसानों में आर्थिक विषमता बढ गई है, निर्धन वर्ग और निर्धन बन गया है और भूमिहीन श्रमिकों की ओर चला जा रहा है। समाज में एक भयकर वेकारी का रूप सामने आएगा और योजनाएं स्वप्न मात्र नजर आएंगी और यह प्लानिंग जिसके बारे में हम बात करते है वह प्लानिंग निरर्थक हो जाएगा।

रूरल पीपुल की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए फोर्थ प्लान में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल–पूर्ति, विद्युतीकरण एव आवासीय योजना के बारे में बड़ी रकम भी लगाई गई है, उससे कई क्षेत्रों में सुधार भी हुआ है लेकिन गांवों में कोई उद्योग धंधे नही है जिससे ग्रामीणों को कोई रोजगार नहीं मिलता है, उनको रोज़ी देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने अपनी योजना में यह बात कही है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको सप्लाई करने का इंतजाम हम करेंगे लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी ग्रामीण गरीब लोगों के पास नही है। हम कई बार देखते हैं, फेयर प्राइस शाप्स में अनाज है लेकिन रोज़ी न होने से उनके पास पैसा नही आता है और पैसा न होने से उनके पास सामान खरीदने के लिए परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो यही है कि उनको हम रोज़गार के साधन कैसे प्राप्त करा सकते हैं। चार-पांच प्लान्स आज तक बने हैं लेकिन खेद के साथ कहना पडता है कि प्लान्स में उन लोगों की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। मेरा तो सुझाव यह है कि प्लानिंग कमीशन के जो कर्मचारी है उनको इसके लिए स्टडी ग्रूप बनाना चाहिए और उनको किताबें लेकर स्टडी करने में लगा देना चाहिए। किसान की बात, गरीब की बात हर एक करता है लेकिन गरीबी क्या है, किसान का दुख क्या है, यह प्लानिंग कमीशन आज तक नहीं समझ सका। सब लोगों ने देहात के बारे में जो कुछ कार्यक्रम दिया है, उसमे शहर और देहात में भेदभाव किया गया है। एक हेल्थ, स्वास्थ्य, के बारे में ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पापुलेशन देहात में रहती है, लेकिन हेल्थ का बजट देखा जाए तो देहात में

10 प्रतिशत भी उसके लिए खर्चा नहीं होता है। देहात में पानी का इंतजाम करना चाहिए, जल-पूर्ति का इंतजाम होना चाहिए, यह कहा जाता है तो पापुलर कांट्रीब्यूशन मांगा जाता है लेकिन शहर में जो बडे बडे नल लगते हैं उसके लिए पापुलर कांट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाता है, स्कूल बनाना है तो पापुलर कांट्रीब्यूशन मांगा जाता है, जो भी चीज बनानी है पापुलर कांट्रीब्यूशन मांगा जाता है। यह भेदभाव क्यों है रूरल पीपुल और अर्बन पीपुल में? ये इतिहास मैंने आपके सामने रखा है, जो विलो पावर्टी लाइन हैं उनका। इसलिए मैं चाहता हूं कि पापुलेशन बेसिस पर प्लानिंग कमीशन ने सारा पैसा देने का इंतजाम करना चाहिए।

मैं एक-दो बातें आपके सामने रखकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

आखिरी में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह सब होने के बावजूद कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, इस बारे में सुझाव देना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। इसके पहिले मैं यह मांग रखता हूं कि गरीब लोगों के लिए रोजगार और आय की व्यवस्था करने की योजना बनाई जानी चाहिए। आप कहेंगे कि गरीब लोगों के लिए तो कई योजनाएं बनाई गई है। मैंने जैसा कहा कि इस तरह के गरीब लोगों की जो तादाद है उसके बारे में प्लानिंग कमिशन के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भूमिहीन लोग है, खेतिहर लोग है, उनको खेती उपलब्ध कराई जाय और उनको न्यूनतम वेतन दिया जाय। हमारी तो यह मांग रहेगी कि जो रोजगार मांगता है, जो काम मांगता है, उसको काम और रोजगार मिलना चाहिए। यह चीज तो कम से कम सरकार की ओर से हो जाना चाहिए।

आप सब लोग देहातों की परिस्थिति को जानते ही हैं। अगर वर्षा 7–8 दिन तक हो जाती है तो उन लोगों के पास कोई रोजगार नही रहता है और उनको भूखा रहना पड़ता है। उनको साल में काम देने की एम्पलायमेंट गारन्टी मिलनी चाहिए और इसीलिए मे कहता हूं कि इस बारे में कोई गारन्टी स्कीम की योजना होनी चाहिए और हर जगह पर यह स्कीम लागू की जाय।

आखिरी में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के प्रत्येक नागरीक के लिए कुछ न कुछ आय कमाने की योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए रोजी और रोटी की योजना होनी चाहिए। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरीक के लिए कुछ न कुछ आय की व्यवस्था करने के लिए जो भी योजना बताई जाएगी वह "रोटी-रोज़ी की योजना होगी ताकि उसको रोजी और रोटी प्राप्त हो सके। हर एक आदमी को कम से कम रोटी और रोजगार अवश्य प्राप्त हो जाय, कम से कम इस तरह की कोई एक अच्छी योजना बना दी जानी चाहिए जिससे उसके लिए मजदूरी की व्यवस्था और काम की व्यवस्था हो सके। अतः सर्वप्रथम सरकार का ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए और इस चीज की चिन्ता करनी चाहिए ताकि प्रत्येक भारत के नागरिक को रोटी और रोजगार प्राप्त हो सके। हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, अतः मुख्य समस्या उसके लिए रोजगार जुटाने से है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर बेरोजगारी और सामयिक अल्प रोजगार की काली घटाएं छाई हुई है। इस समस्या से निबटने का सबसे सहज उपाय यह है

[श्री देवराव सिवराम पाटिल]

कि बहु फसली पद्धति की व्यापक रूप से व्यवस्था की जाय क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था करने से ही ग्रामीण श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार मिल सकता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): For the benefit of new Members, I will read Rule 161. Under Rule 161, a Member can speak on a private Member's Resolution for 15 minutes. Since the number of speakers is big, I hope the Members will co-operate with the Chair.

SHRI D. THENGARI (Uttar Pradesh): Sir, this is a very important problem and we are discussing it rather 25 years late. Our Planning Commission has not taken cognizance of this problem and therefore we find that our rural areas are almost totally ignored. Is it not a fact that thousands of villages are not having access even to drinking water in the summer season? The very first economic problem before the country was what should be the character of our industrialisation. It is well known that the developing countries cannot profitably imitate the developed countries in point of technology, location and size of the industry. Sir, a British economist, Dr. Schumacher, toured the South-East Asian countries and came to the conclusion that the Western technology type of production will not be useful in Asian conditions and, therefore, he evolved an intermediate technology which is now being named as appropriate technology the peculiar characteristic of which is that without decreasing considerably the efficiency of the industry the employment potential should be increased and that should be the characteristic of our technology. Therefore, he has insisted upon the location of industries in the medium cities and also in the rural areas and he has suggested decentralisation of industries and also he has suggested that in the existing techniques of our traditional industries there should be some innovation, technological innovation, without decapitalising our managerial skill and the skill of our traditionally self-employed persons and also the small capital available in the rural areas.

Sir, we are having the problem of investment now. It is so because we are concentrating only on heavy industries. If we channelise all the small sums available in the rural areas into industrial investment through small-scale savings and again investing them in small-scale industries, the very industrial map of India would have been altered. Therefore, I suggest that an expert committee should be appointed to study the technological and locational aspects of our industries. I say this because in the rural areas there is not sufficient electrification and we have not tried to imitate the Japanese way. In Japan, Sir, electricity is there in all the huts in the villages and the hamlets and the processes of production are decentralised and in every hut some part of a commodity, some part of an article, is being produced according to specifications and standards and all such parts produced separately are assembled at one place and in this way, Sir, the agricultural population which is under employed and unemployed for at least five or six months in a year gets additional employment without losing its contact with its land. If we adopt some such techniques, it is possible for us also to decentralise the processes of production and in this fashion industrialisation suited to our conditions can take place in our rural areas.

Sir, our entire planning has been heavily loaded in favour of the richer classes using luxury goods and it is known to the Planning Commission that the processes of production also condition the processes of distribution. Our Government is talking of socialism and under socialism there should be equitable distribution of wealth. Now, Sir, to say that with very high-production techniques we will increase our luxury goods and thus our GNP will be increased and our total national wealth will be increased and once it is increased, we will try to distribute it equitably is, I think, a self-defeating theory. As a matter of fact, if there is a ban on luxury goods and if we give impetus to the production of consumer goods, naturally, Sir, employment will increase because the consumer goods can be produced by low-production techniques in the rural areas and then, naturally, the income distribution problem will be solved. Now, with the production of luxury goods, there is concentration of wealth in the cities and from the rural areas people are inclined to flock to the cities for getting employment. Urbanisation, over-urbanisation, has its own problems. Because of over-urbanisation, Sir, those who come from the rural areas are cut off from their moorings and they do not have

he family life and its affects their total personality and also the problems of sanitation and transport and other such problems we have not been able to solve in the cities. Moreover, we also find that because of over-urbanisation our cultural standards are also going down. Instead of concentrating our industries in the urban areas, if we decentralise our industries in the rural areas, it will be possible for us to have equitable distribution of wealth and, at the same, to have a healthier atmosphere. You know, Sir, that nowadays even the Western countries have taken cognizance of the fact that industrialisation with no regard for the ecological aspects is a dangerous thing and is detrimental to the health of mankind as well as to the other living creatures. This is detrimental to the health

4 P. M. of the mankind as well as of all living creatures. In the West, special committees are being appointed in different countries to solve ecological problems. Our industrialization has also created ecological problems. Only in Kanpur, it was stated by experts, as many as 3,000 chemical substances, which are not helpful to living things, are there in the atmosphere. Now, if the ecological problems are to be solved, the only way is to decentralise our industries. But, Sir, in blind imitation of the West, we have brought in heavy industries. And now we find that we have reached a stage where we cannot fully utilize the capacity of installed machinery. Idle capacity has also become another problem before our country. If the technology is changed—I am sure, our technologists, if properly engaged, are competent enough to take care of this problem—if technology is changed to suit the Indian conditions, it should be possible for us to have widely scattered small and medium size industries throughout the rural areas so that our problems of economics and equality will be solved, and, Sir, simultaneously the problems arising out of over-urbanisation which are mainly cultural in character, will be solved. Therefore, I urge that an expert committee should be appointed. I support this Resolution. This Expert Committee should go into the entire problem and see that our industries are decentralised and incomes properly distributed—not through any mechanism of governmental machinery but through the very process of production. so that there is equitable distribution of wealth.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): Iam happy that the hon. Member has not yet lost his faith and confidence in the constitution of new committees....

(*Interruptions*).

श्री श्रीधर वासुदेव राव घावे (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, आपके सामने यह जो सवाल रखा है शंकरलाल तिवारी ने यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो मसले हैं। एक तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार विषमता बढ़ रही है—आर्थिक भी बढ़ रही है और सामाजिक भी बढ़ रही है। मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सामाजिक समता के बारे में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सामाजिक विषमता इतनी बढ़ गई है कि वहां अभी भी हरिजनों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं होता है। हमारे प्रान्त महाराष्ट्र में बावड़ा में हरिजन और नान-हरिजनों का झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, कहीं हरिजनों का अलग कुआं है और बाकी का अलग कुआं है और भी कई तरह की विषमतायें हमारे देश में चल रही हैं। आन्ध्र में हरिजनों को जलाने के बारे में अभी बात हुई थी। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विषमता जो बढ़ रही है इसको बड़ा महत्व देना चाहिए। इतना ही नहीं आदिवासी लोग जो नासिक में और कई जगह रहते हैं, ट्रायबल एरियाज में, वहां चूंकि वह बहुत गरीब हैं, इसलिए फारन मिशनरीज़ ने वहां जाकर केन्द्र किया है और वहां शिक्षा के माध्यम से दूसरे काम चलते हैं और इसीलिए यह सामाजिक और आर्थिक विषमता यहां बढ़ रही है।

वहां आदिवासी लोगों के लिए, उन गरीब किसानों के लिए जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी आमदनी कम है, जिनको तनख्वाह कम मिलती है,

[श्रीधर वासुदेव राव धावे]

शिक्षा की कोई व्यवस्था नही है, उन के लड़को के लिए वहां शिक्षा का कोई वातावरण नहीं रहता। उन की शिक्षा का प्रबंध करने जा कर केवल यह कह देने से कि 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जायगी, काम नहीं चलेगा। इतना ही काफी नहीं है। उन का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए वहा आप को पब्लिक स्कूल खोलने चाहिएं, उन के लिए कैन्टीन्स और होस्टल्स का प्रबंध करना चाहिए। इस की आज आवश्यकता है। जो आज विषमता का, सामाजिक विषमता का सवाल है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और आर्थिक दृष्टि से भी यह महत्व रखता है। जहां जहां कैंटीन्स और होस्टल्स हैं वहां वहा छुआछूत कम हो गयी है, लेकिन देहातों में जहां औद्योगीकरण नही हो पाया है वहा छुआछूत की भावना बहुत अधिक है और जब तक देहातों में औद्योगीकरण नहीं होगा हमारे यहां देश में समानता की भावना का निर्माण नही होने वाला है। इस लिए जो भारी उद्योग हैं वह उन रूरल एरियाज में होने चाहिएं जैसा कि अभी पाटिल साहब ने कहा। इस लिए यह आवश्यक है कि वहां ऐसे उद्योग शुरु किये जायें कि जिन में वहां के लोगो को रोजगार मिले। यह बात यहां कही गयी कि चूंकि पब्लिक सेक्टर में लोगों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है इस लिए रेलवे वाले ज्यादा तनख्वाह की मांग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पब्लिक सेक्टर के उद्योग उस क्षेत्र में हैं कि जिन में मजदूरों की तनख्वाह रेलवे मजदूरों से भी कम है। मध्य प्रदेश मे मेगनीज का जो उद्योग है वहां मेगनीज ओर आफ् इंडिया पब्लिक सेक्टर में चलती है। वहां 6 महीने पहले तक ढाई रुपया मिनिमम वेज थी। अभी वह 4 रुपया की गयी है। पूरे महीने में एक मजदूर को 120 रुपया तनख्वाह मिलती है और यह देश का बड़ा प्राइज्ड पब्लिक सेक्टर है। स्टील इंडस्ट्रीज में यहीं से मेगनीज जाती है। उन में मेगनीज का उपयोग होता है। तो पब्लिक सेक्टर जो रूरल एरियाज मे खुले हैं, मैं चाहूंगा कि उन में कम से कम मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिले और इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में खोले जाने की आवश्यकता है। आप के सामने जो और बातें मै कहना चाहता हूं उन में एक यह भी है कि देहातों में जो आज परिस्थिति है उस में वहां बाइयों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों को दो रुपया मिलता है तो स्त्रियों को पौने दो रुपया मिलता है। समान काम के लिए समान वेतन का आयू एक्ट ओका नियम है। उस का भंग सब से ज्यादा देहातों में ही होता है। मैं चाहता हूं कि जैसा कि नये फाइव इयर प्लान के अप्रोच डाकुमैंट में कहा गया है, इस विषमता को कम किया जाना चाहिए और यह जो स्त्री और पुरुष का भेद है तनख्वाहों में वह वहां पर समाप्त किया जाना चाहिए। इस बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कई जगह देहातो में किसान वेतन फिक्स किया हुआ है लेकिन जहां वेतन फिक्स किया गया है उस पर अमल कराने के लिए पूरा सा कोई यंत्र वहा नहीं है। तो केवल वेतन फिक्स कर देने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक उस के लिए रेवेन्यू आफिसर्स को अधिकार नहीं रहेगा तब तक मजदूरों को वह वेतन मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रूरल एरियाज के बारे में अधिक ध्यान दिया जाय। केवल एक राज्य है हरियाणा जहां कि

बिजली की सप्लाई सभी देहातों में भी पहुंच गयी है, लेकिन हर जगह एलेक्ट्रे-सिटी, बैंक और पोस्टल फैसिलिटीज उन को अभी नहीं हैं। यह फैसिलिटीज कम होने के कारण ही वे लोग शहरों में चले आते हैं। देहातों में शिक्षा का प्रचार भी बहुत कम है इस लिए भी लोग शहरों में ज्यादा जाते हैं।

काम कुछ मिलता है, कुछ नहीं। मेरा कहना है कि दोनों हाथों को काम मिलना चाहिए। सेलरी वर्कस तैयार होने चाहिए। इसकी एक क्लार्स तैयार होनी चाहिए। नये उद्योग अगर वहां खोले जाएंगे तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विषमता बढ़ रही है उसका प्रमुख कारण यह है कि रूरल एरिया में आज रोजगार के साधन नहीं हैं। शहरों में उद्योग होने से जितनी एम्पलाए-मैन्ट गारण्टी है उतनी गांवों में नही है। इसलिए गांवों में रोजगार योजना अवश्य बनानी चाहिए। ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे उनको काम भी मिले और जो उनकी सिक्योरिटी आफ जाब है वह भी हो। इतना ही कहकर मैं, जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और जैसा कहा गया है कि एक कमेटी नियुक्त की जाए, उसकी भी सिफारिश करता हूं।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश): मैं जानना चाहता हूं कि मुझे 10 मिनट दिए गए हैं या 15 मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): जितनी जल्दी आप खत्म कर सके उतना अच्छा है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा: मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं उतने समय में ही अपनी स्पीच खत्म कर दूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देहातों के लिए 25 साल में जो कुछ हुआ है उसको एक ही ढंग से गांवों की बेबसी आदमी कह सकता है:

"सितम की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं
ये उनकी बदगुमानी है कि फरयादी समझते हैं।"

जितने सितम गांवों के ऊपर ढ़ाए गए हैं उतने सितम शायद सारे देश के ऊपर नहीं। यह केवल चन्द लोगों के रोजगार का सवाल नही है उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें चार बुनियादी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जो उपेक्षा गांव की की गई है, देहात की की गई है, याद रखिए 70 फीसदी हमारे देहातों में जो लोग हैं उनकी उपेक्षा की गई है और उसकी उपेक्षा करने के मायने हैं जो मास्टर हैं इस देश के उनको आपने उपेक्षित किया।

इस देश में जनतंत्र की रीढ़ क्या है? सबसे पहले बुनियादी सवाल यह है कि यहां के बिजनैस तबके से जनतंत्र की रीढ़ नहीं बनती। यहां के नौकरशाही से जनतंत्र की रीढ़ नही बन सकती। यहां पर एक ही तबका है वह है गांव का जिसका रक्षित स्वार्थ है इस जनतंत्र के संचालन में। जिस किसी व्यवस्था के पीछे किसी का रक्षित स्वार्थ नहीं होता है, जिसका रक्षित स्वार्थ नहीं होता वह व्यवस्था कभी कामयाब नहीं हो सकती। इस देश में जनतंत्र के संचालन के लिए रक्षित स्वार्थ अगर किसी का है तो वह है देहात की जनता का। उसके जीवन-मरण का सवाल इस जनतंत्र के साथ संलग्न है। उसकी उपेक्षा के मायने हैं आपने जनतंत्र की उपेक्षा की है। जनतंत्र की बुनियाद को खोखला कर दिया है।

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

दूसरा बुनियादी सवाल है हमारी समस्याएं। आदमी जब पैदा होता है तो भूख लेकर पैदा होता है--एक स्वतंत्रता की भूख और दूसरी पेट की भूख। ये दोनों भूख ऐसी हैं जो जन्मजात हैं। इन दोनों में पेट की भूख पहले आती है। उसके भरने के बाद आजादी की भूख पैदा होती है। राणा प्रताप पेट के लिए नही मरे, गुरु गोविन्द सिंह पेट के लिए नहीं मरे, गारी बोर्डी, सुभाष पेट के लिए नहीं मरे, आजादी के लिए मरे। इन्सान में आजादी की भूख और पेट की भूख दोनों साथ-साथ पैदा होती है। साम्यवादी व्यवस्था में रोटी का सवाल तय हो सकता है लेकिन व्यक्ति की आजादी समाप्त हो जाती है।

हो सकता है कि आप किसी पूजीवादी व्यवस्था में ज्यादा आज़ादी दे सकें लेकिन करोड़ों आदमियों को जितना पूंजीपतियों के हाथों आर्थिक गुलाम बनना पड़ता है उसको आप समझ सकते हैं। दोनों में से कोई भी व्यवस्था आप लें, इस मुल्क का निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि आप वह आर्थिक व्यवस्था रखें कि जिसमें आर्थिक सत्ता केंद्रित न हो। राजनैतिक सत्ता आप केंद्रित करते चले जा रहे है, आर्थिक सत्ता भी आप केंद्रित कर लें तो जनतंत्र मर जाएगा और आदमी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा वह गुलाम बन जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है, देश के जनतंत्र के लिए जरूरी है, कि आप आर्थिक सत्ता को विकेंद्रित करें। और क्या ज़रूरत है हमको चीनी मिल चलाने के लिए। बड़े पूंजीपति की जब आप करोड़ों की चीनी मिल चलाएंगे तो निश्चय है कि आप करोड़पति ढूंढेंगे चाहे वह सरकार करोड़पति का काम करे, चाहे वह बिड़ला करे। क्यों न इन चीनी मिलों को तोड़ कर गांवों में बिजली के कोल्हू दिए जाएं? क्यों नहीं उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए? जिस समय कांग्रेस की और भा० क्रान्ति दल को मिली-जुली हुकूमत हमारे सूबे में चल रही थी, चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे, उन्होंने लिखा आदरणीय बहन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी को, कि जरूरत इस बात की है कि हमारी कपड़ा मिलें जो कपड़ा तैयार कर रही हैं उसको आप बाहर बिकने के लिए भेज दीजिए; देश के कंजम्शन के लिए जो कपड़ा होगा वह हमारे हैंडिक्राफ्ट से, हैण्डलूम्स हमारे पावर लूम्स से तैयार होगा। उससे करोड़ों करोड़ों नौजवानो, पढ़े, वग़ैर पढ़े की रोज़ी का सवाल हल होता है। दौलत बढ़ कर के गांवों की तरफ जाती है। लेकिन आप दौलत को कुछ हाथों में कांसेंट्रेट कर रहे हैं; आप ऐसा सिस्टम एडाप्ट करते चल रहे है कि जिसमें सारी सत्ता बिखरने के बजाए चंद लोगों के हाथ में आए; आप चाहते है कि यहां बैठ कर उसका डिस्ट्रिब्यूशन जिस तरह से चाहें करें एक हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है कि हम सत्ता को केंद्रित करके, धन को केंद्रित करके उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं चाहे वह महाराजा विक्रमादित्य ही धरती पर उतर कर क्यों न आएं। स्वाभाविक है, हम पैसे को नहीं, रोटी को नहीं बांट सकते; वरन रोजी हमको बांटनी पड़ेगी और अगर यह रोज़ी बांटने का रुख देहात की तरफ जाता है तो देहात की समस्या हल होती है। क्या वजह है, देहात लुटता जा रहा है? ये सारे शहर देहात के खण्डहरों के ऊपर, उसकी हड्डियों के ऊपर निर्मित हो रहे हैं? आप इस बात को भूल रहे हैं आज के हमारे गांवों बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उसमें जो पढ़े-लिखे

नौजवान हमारे निकलते हैं सब शहरों की गलियों में भीख मांगते फिरते हैं आपसे नौकरी के लिए, रोज़ी के लिए। अगर गांव का मक्खन, पढ़े लिखे नौजवान, गांव छोड़ कर भागते हैं शहर की गलियों में लुटने और पिटने के लिए, तो उस गांव को कौन ऊपर उठाएगा? ये सरकारी अहलकार गांवों को उठाएंगे या कंस के सिपाही? ये अथासुर बकासुर गोकुल को लूटने के लिए है, गोकुल का निर्माण करने के लिए नहीं हैं। कृष्ण के सिपाही आप पैदा नहीं करेंगे। जो गांव में बैठकर स्वयं खायेगा खेती करके, जब रोजगार करके, उद्योग करके देश को रचनात्मक नेतृत्व देगा, वही प्रजातंत्र का रक्षक होगा और वही देश को नयी दिशा देगा। आप उस गांव को भूल गए जो देश की 20% अबादी रखता है। मैं नहीं कहता, आपको रेलवे इंजन बनाना है बनाइए—हमें कोई ऐतराज नहीं—हवाई जहाज बनाना है आप बनाइए। लेकिन कपड़ा है, शीशे का सामान है, लकड़ी, लोहे का सामान है, मोटर के पुर्ज़े हैं; साइकिल का सामान है, चीनी के कारख़ाने हैं, क्यों नहीं ये छोटे पैमाने पर देहातों में हो सकते? यदि जापान इस रास्ते को ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। लोग कहते हैं अग्रिकलचरल इकानामी देहात की जिस तरह से चल रही है यह गरीब देश की निशानी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज के विज्ञान के लिए क्या यह संभव नहीं है कि वह उत्पादन की विधि को, उत्पादन की व्यवस्था को इस ढंग पर लगा दे कि बजाए बड़े बडे कारखानों के. जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप पनपाते हैं, हज़ारों आदमियों के पढ़े अनपढ़ें के हाथ में रोजी लगे। कैसे आप इन पढ़े लिखों की बेरोज़गारी का सवाल हल करना चाहते हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, सन् 1951 के सितम्बर महीने की बात है, मैं उस समय सूवा कांग्रेस का मेम्बर था, त्रिलोकीनाथ हाल लखनऊ में मीटिंग हो रही थी, आदरणीय नेहरू जी उस दिन आए थे, पण्डित पंत जी का एक प्रस्ताव आया, मैं संयोग से एक इंटर कालेज का प्रिन्सिप्ल रहा हूं, तालीम के बारे में जानता हूं, पढ़े लिखों की समस्याओं को समझता हूं, मैंने उस समय कहा था: याद रखिए, जिस तरह की तालीम आप दे रहे हैं, जिस तरह से बेरोज़गारों की जमात आप पैदा कर रहे हैं, 25 साल पहुंचते पहुंचते इन बेरोज़गारों को आप रोजी, नौकरी नहीं दे सकेंगे।

नौकरी देकर भी आप उसका स्टैन्डर्ड पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान देश को रचनात्मक नेतृत्व नहीं दे सकता है और वह देश का कुछ फायदा नहीं कर सकता है। इस चीज से तो उसका दिमाग भ्रामक बन जायेगा और इसका नतीजा यह होगा कि आजादी के 25 साल के बाद वह नौजवान कभी रेल गिरायेगा, कभी मिनिस्टर की कार खींचेगा और कभी कोई दूसरा ऐसा ही कार्य करेगा।

उपसभाध्यक्ष (**श्री वी० वी० राजू**): मैं माननीय मेम्बरों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आज पांच बजे खत्म हो जायेगा। इस प्रस्ताव पर बोलने वालों की क्यू लगी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा: मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूगा। कुछ वर्ष पहिले की बात है नेहरू जी ने यह आह्वान किया था कि पढ़े लिखे लोगों को गांवों की तरफ मुड़ना चाहिए।

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

बात तो सही है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोगों को गांव की तरफ मुड़ने के लिए कहते हैं, तो आप उनके लिए रास्ता क्या देते हैं। गांवों में रोटी, रोजी की कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। वहां पर जो खराब आर्थिक व्यवस्था है उसको खराब बनाने की ही हम कोशिश करेंगे, अगर उनके लिए कोई आर्थिक और रोजी की योजना बनाकर नहीं दी जाती वहां पर उसका कोई भविष्य नही है। वह शिक्षित व्यक्ति गांव की तरफ क्यों जाय? आपने उसके लिए वहां पर क्या व्यवस्था कर रखी है? केवल नारे लगाने से पढ़ा लिखा समाज गांवों में नहीं जायेगा। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह सवाल एक बुनियादी सवाल है, जिसको अगर आप हल नहीं कर सकते हैं जनतंत्र की रक्षा के लिए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के लिए, पूंजीपति और नौकरशाही से देश को बचाने के लिए तो फिर ईश्वर ही इस देश का रक्षक हैं। आज कोशिश यह होनी चाहिये कि हम विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ़े और इसी तरह की हमारी आर्थिक व्यवस्था भी होनी चाहिये।

इस प्रस्ताव में जो यह बात रखी गई है कि इस बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी विठलाई जाय जो इन सब बातों को मद्देनजर रखे और कोई रास्ता निकाले। अगर 5 – 10 साल के अन्दर जो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी रोटी और रोजी का प्रबन्ध हम कर सकते हैं, तो यह देश के जो नौजवान हैं, वे देश को नेतृत्व दे सकते हैं और देश को प्रगति की तरफ बढ़ा सकते हैं तथा इससे देश का कल्याण हो सकता है। यह प्रस्ताव कुछ देर से आया है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि अगर इस बारे में कोई कमेटी विठलाई जायेगी तो फिर कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): उप-सभाध्यक्ष महोदय, श्री तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और श्री पाटिल जी ने जो संशोधन दिया है, उस संशोधित प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। गांवों के भी कुछ एक्सपर्ट कहे जाते है, विशेषज्ञ कहे जाते हैं, लेकिन देहाती विशेषज्ञ जो है, वे किताबी विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि 25 साल की तरक्की के बाद भी हिन्दुस्तान की ग्रामीण जनता की जितनी तरक्की होनी चाहिये थी, उतनी तरक्की नहीं हो पाई है। उसका सब से बड़ा एक कारण यह है कि अंग्रेजी राज से पहिले हिन्दुस्तान की देहात की आबादी का कुल 60 प्रतिशत खेती-बाड़ी पर निर्भर करते थे। 40 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो कारीगर या दूसरे कामधन्धों में लगे हुए थे। 25 साल के जमाने में हमने यह देखा कि जो मजदूर चमड़े का काम करता था, वह किसी कारखाने में पहुंच गया है। जो देहात का आदमी कोई बर्तन बनाता था, उसने किसी बड़े कारखाने में शहर में काम शुरू कर दिया है। इसी तरह से जो कपड़ा बनाता था, उसका भी कामधन्धा खत्म हो गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि गांव से आदमी शहर की तरफ रोजी के लिए चला जा रहा है। आज देश में यह नारा लगाया जा रहा है कि जो भूमिहीन है, उसको जमीन दी जाय। लेन्ड आर्मी बनाई जाय। इस तरह के अजीब अजीब नारे लगाये जा रहे है।

इस देश के अन्दर खेती करने वालों की फौज है। आज देश के अन्दर जरूरत इस बात की है कि जितने

लोग खेती पर निर्भर है उनमें से कुछ आदमियों को दूसरा धन्धा दिया जाय। 25 साल में हमने जिस ढंग से काम किया उसका नतीजा यह हुआ कि जो पढ़ा वह देहात छोड़कर भागा। आप जानते हैं मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसमें देहात के अन्दर तरक्की हुई, हर गांव के अन्दर बिजली है और 60-70 फीसदी गांव ऐसे हैं जहां पक्की सड़के हैं, जहां आज बसें जाती हैं, जहां 4-5 गांव के पीछे स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि देहात की तरक्की के लिए जिस ढंग की योजना बननी चाहिए थी वैसी योजना हमारे देश में अभी बनी नहीं। जैसा अभी बताया देश में 80 फीसदी आदमी देहात में रहते हैं और उनमें से 70 फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं। ये बड़े बड़े विशेषज्ञ, चाहे योजना मंत्री हैं, वित मंती हैं, चाहे प्रोग्रेसिव है, चाहे दूसरे भाई हैं, चाहे सी० पी० आई के है, चाहे सी० पी० एम के हैं, उनको फिक्र एक बात की है कि रुपया कितना छपा, वे सब कागज के हेरफेर में रहते हैं। रुपया कम छपा या ज्यादा छपा, इससे तरक्की में फर्क नहीं पड़ सकता, देश की हालत नहीं बदल सकती। बड़े मुकाबले किए जाते हैं हिन्दुस्तान के दूसरे देशों से। मैं योजना मंत्री जी से चाहूंगा कि जरा यह भी आंकड़ा दें कि अमरीका में फी आदमी रुपए का कितना प्रसार है और हिन्दुस्तान में फी आदमी कितना आता है। इसी तरह से दूसरे देशों के अन्दर फी आदमी कितना पैसा पड़ता है और हमारे यहां कितना पड़ता है? सारा आर्थिक दायरा ऐसा बना दिया कि रुपया ज्यादा हो गया है, मंहगाई हो गई है, तरक्की नहीं हो सकती, योजना का काम रुक जायगा। योजना कामयाब हो सकती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। पिछले दो साल में क्या मुश्किल हुई? हमारे देश के अन्दर अनाज की पैदावार घटी। देश के 70 फीसदी लोग खेती के काम पर लगे। खेती की कुल पैदावार मिली देश की आयका 48 फीसदी और सरकार ने खेती की तरक्की के लिए खर्च किया 15 फीसदी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। वह जमाना निकल गया जब दस्तखत करने से अमरीका से अनाज मिल जाता था। अब तो अमरीका से 290 रुपए क्विन्टल गेहूं मिलेगा और वह भी दस्तखत से नहीं मिलेगा, हिन्दुस्तान का सामान बाहर बेच कर मिलेगा। अमरीका ने जो हमको अनाज दिया हम मशकूर हैं कि उससे हमारे यहां अमन और शांति कायम रही, लेकिन उससे एक अफीम जैसा नशा हमारी सरकार को हो गया और हमारे विशेषज्ञों को हो गया और उन्होंने इस प्रकार से काम नही किया कि देश के अन्दर ज्यादा अनाज की पैदावार हो। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं कि देहात और शहर की तरक्की का इनका माप कैसा है। उपसभाध्यक्ष जी, मल्टी-परपज प्रोजेक्टस के अन्दर कुछ रुपया बिजली के हिसाब में लिखा जाता है, कुछ सिंचाई विभाग के हिसाब में लिखा जाता है। हमारा केन्द्रीय एक्ट है, उस कानून के तहत ये देश की सरकार बिजली बोर्ड से कर्जा वापस नहीं लिया जा सकता। जो विशेषज्ञ थे वे शहर वाले थे, उन्हें यह ख्याल नहीं था कि एक एसा भी वक्त देश के सामने आएगा जब बिजली देहात में भी जायगी। उनको यह भी ख्याल नहीं था कि 48 फीसदी बिजली हरियाणा में खेती की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा सारा पैसा तमाम वापस करे जो खेत में पैदा करें।

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

इरिगेशन का, सिंचाई विभाग का 15 हजार करोड़ रुपया बिजली बोर्डों के ऊपर, बिजली पैदा करने और उसका प्रसार करने पर देश में खर्च आई साढ़े तीन हजार रुपया खर्च हुआ। सिंचाई विभाग पर मेरे भाई मिश्रा जी चले गये, बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़ी बात कही उन्होंने कि डेढ़ सौ करोड़ रुपया साल का घाटा है। 58 लाख रुपये का घाटा तो 1950-51 में था और जो आज हमारी सिंचाई की योजनायें हैं उनके अन्दर और सारी देश की सरकारों को डेढ़ सौ करोड़ रुपया और जो ब्याज की उनसे आमदनी होती है और जो ब्याज देना पड़ता है, वर्किंग ऐक्सपेंसेज लेकर, कुल डेढ़ सौ करोड़ रुपया का घाटा है। लेकिन वह भूल जाते हैं इस बात को कि वह हरियाणा और पंजाब जिसके भाखड़ा के ऊपर डेढ़ सौ करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 500 करोड़ रुपये का अनाज हर साल पैदा करता है। तो उसका व्याज का हिसाब खाता है। मैं आपकी मार्फत योजना मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हमने समाजवाद कायम करने का इरादा किया है, प्रस्ताव किया है, लेकिन हमारा वही पुराना मर्केंटाइल तरीका है इकानामी का। रुपये का नोट छापते हैं रुपये की सेंक्यूरिटी पर। भाखड़ा की सेंक्यूरिटी पर छापिये, सड़कों की सेक्यूरिटी पर छापो, न कर्जा वापस लेना पड़ेगा न झंगड़ा रहेगा। हमारे देश के अंन्दर जो कारखाने थे उसमें शहरों के अन्दर रुपया लगा, 2,900 करोड़ रुपया सरकारी कारखानों में सरमाये का लगा वह रुपया तो वापस नहीं लेना है, लेकिन नहर का रुपया वापस लेना होगा। नतीजा है कि – हमारे कमलापति जी बैठे हैं वह मुख्य मंत्री रहे, चह्वाण साहब भी रहे और ब्रह्मानन्द रेड्डी भी रहे और उन्होंने कहा कि मजबूरन सिफारिश करनी पड़ी कि अगले 5 साल के अन्दर 1900 करोड़ रुपया जो की प्रदेश सरकारो की केन्द्रीय सरकार को वापिस करना था जो कर्जा लिये हैं उनको जिस हिसाब से देना चाहिए था वह अदा नहीं कर सकतीं। देश की आर्थिक सोच गलत है। उसको हम बदलें। रुपया छापने की नीति को बदलें। जो सैक्यूरिटी है, जो सोने की सेक्यूरिटी थी पहले गोल्ड सेक्यूरिटी पर नोट छापे जाते थे, आज सेक्यूरिटी हमको चाहिए जो देश में काम बनते हैं उनके ऊपर। ढाई सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हो तो उसके ऊपर छापें।

(Time bell rings)।

उपसभापति जी दो-तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): हर एक को मौका देना है।

श्री रणबीर सिंह: मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देहात की तरक्की और देश की तरक्की इस बात पर निर्भर है कि देश की पैदावार बढ़े। इसलिए मैं कहता हूं कि पाटिल साहब का संशोधित प्रस्ताव का हम इसलिए समर्थन करते हैं कि आज के विशेषज्ञ हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकते। वह मानते हैं कि किसान बहुत ज्यादा साहूकार हो गया। वह कोई टैक्स ही नहीं देता। इनडाइरेक्ट टैक्स तीन चौथाई है और किसानों की आबादी 70 फीसदी है। वह टैक्स नहीं देता और 6 हजार या 7 हजार रुपया जो पाता है वह टैक्स देता है। वह कौन सा टैक्स देता है? कोई किसान ऐसा नहीं हो सकता। फी एकड़ जमीन वाले को भी मालिया देना पड़ता है। लेकिन

सरकार के तनख्वाहदार आदमी जो 6 हजार रुपया तक पाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं है और वह कहते हैं कि वह टैक्स देता है।

एक अजीब सोच है। इस आर्थिक सोच को छोड़ना होगा। इस आर्थिक सोच को बदल कर देश के आर्थिक ढांचे को बदलना होगा। आज जितने भी काश्तकार हैं, मार्जिनल काश्तकार हैं, उनकी तरफ से मैं योजना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पांच साल में उनके लिए जितना पैसा रखा है, 680 करोड़ रुपया उनको देने की बात आपने कही है, मैं चाहता हूं कि आप यह सारा पैसा उन को एक ही साल में दे दें ताकि इस से वह अपने यहां कुवें लगायें और अपनी खेती की तरक्की कर सकें। इससे एक ही साल में इतना अनाज पैदा हो जायगा। आज हम दूसरों की तरफ अनाज के लिए देखते हैं, आज हम अनाज के लिए सब्सीडी देते हैं। 400 करोड़ रुपया, जैसा कि मैंने कल बतलाया था, बाहर से अनाज मंगाने के लिए या सब्सीडी के लिए हर साल, पिछले 25 साल में हिन्दुस्तान में खर्च हुआ है। मैं योजना मंत्री जी से कहना चाहता हू कि अब देश के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमारी आर्थिक दशा ऐसी हो गयी है उसे देखते हुए हम को अपनी आर्थिक नीति को ऐसी बनाना पड़ेगा कि जिस से देश भी आगे बढ़े और देहात भी आगे बढ़े और जो यह शहर और देहात का भेद ज्यादा बढ़ता जाता है यह कम हो ताकि शहर पर ज्यादा दबाव न पड़े और सब जगह कालेज हों, यूनिवर्सिटियां हों ताकि उन में हमारे बच्चे पढ़ सकें। गांवों में शिक्षा के लिए स्कूल बनाने के लिए लोगों को अपने पल्ले से पैसा खर्च करना पड़ता है शहिरों में उन को सरकार बनाती है। इस में काम बहुत धीरे होता है। इसी तरह से आज सवेरे जिक्र हो रहा था कि जो आगे बढ़े हुए भाई हैं वह आज हिन्दुस्तान के काम को रोकना चाहते हैं, वह आज तरक्की के काम को रोकना चाहते हैं। इस तरक्की को अगर कोई जारी रख सकता है तो वह किसान ही जारी रख सकता है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और देहात को आगे बढ़ाये बिना यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव बहुत साधारण है। आप एक कमेटी बनायें और जितने सदस्य देहात से आते हैं वह उस में हों। यह जो फोबिया कुलक का है या ऐसे ही जो दूसरे विचार हैं उनको आप दिमाग से निकाल दें। या तो हमारी सीलिंग की नीति कामयाब नहीं हुई और अगर वह कामयाब हुई है तो साढ़े 12 एकड़ जमीन में कौन सा कुलक पैदा हो गया। तो आपको इस दिमागी सोच को बदलना होगा अगर हम को आगे बढ़ना है।

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution moved by the hon. Member, Mr. Shankarlal Tiwari, suggests that in view of the increasing gap between the rural and the urban areas, a committee of experts should be appointed. While agreeing with the problem which he has posed, I must say that this is a problem on which intensive deliberations have already taken place during the last 26 years. In fact, the left and democratic parties in this country and various experts have suggested in substantial detail the causes and remedies for this. But if the ruling Congress Party has no political will to solve the problem, that political will cannot be created by appointing another Committee.

Sir, if you look into the basic facts of the situation, you will realise that the *per capita* income of the rural areas was about 27 per cent of the urban *per capita* income during the First Five-Year Plan. But during the Second Plan, the proportion of rural *per capita* income declined to 20 per cent and in

[Dr. K. Mathew Kurian]

the Third Plan, it further declined to 18 per cent. So, the fact that rural incomes are diminishing relative to urban incomes is a fact established by the statistics of the Congress Government itself. The question is, why is it that rural incomes are declining relative to urban incomes and why these imbalances have been created? Sir, during the last decade, for which figures are available through the Census data, we find that the rural poor have become poorer. For example, in the 1971 Census, the proportion of rural population who are landless agricultural labour increased. In fact, this can be explained only by the increasing onslaught of capitalist development in the rural areas, on the one hand, and the continued exploitation of the rural people by the feudal, semi-feudal and other oligarchies in the rural areas, on the other. Who is responsible for this? The Congress Government which ruled this country for the last 26 years, which has introduced land legislation on paper, which had also introduced loopholes in the legislation in order to scuttle such legislation, a Government which increasingly collaborated through foreign private capital and collaboration agreements of imperialist countries, a Government which gave licences to big business in cheerful glee, it is this Government, it is these people, who are responsible for the creation of these imbalances. Unemployment in capitalist countries is considered to be necessary—at least by those who are the spokesmen and the exponents of capitalism—for capitalist development because that provides a reserve army of unemployed people so that the real incomes and wages of those who are employed can be depressed. Price increase is a necessary concomitant of capitalist landlord development, because, without increasing prices and inflationary financing, values from the ordinary people cannot be transferred to the rich saving community. Deficit financing is deliberately chosen by the Government because they want to transfer the value created by the working people to those who are owners of property. This is the class content of their policies relating to poverty, prices and unemployment. Therefore, with such class policies the only result that we can expect is increasing imbalances between urban and rural centres. But I would like to make a distinction, an additional point compared to what the honourable Member who moved the Resolution, made, that it is not true that urban incomes are increasingly becoming higher as compared to rural incomes. In fact, there are segments of urban population who are as poor as rural proletariat. Large segments of urban community today are living with a pittance of wages. In fact, exploitation of urban proletariat has increased during the last decade. For instance, the net output per worker increased by 495 per cent in 1969 compared to 1949. But wages adjusted with rise in cost of living increased only by 24.5 per cent. Therefore, not only the rural proletariat and the rural poor, but also the urban proletariat have been continuously exploited and their incomes have been taken over in the form of inflationary financing, in the form of forced saving. Regional imbalances in this country between regions and States on the one hand, and between districts and areas within each State on the other, are a necessary law of development of capitalism. So long as capitalism rules the roost in this country, you cannot have anything but increasing imbalances between regions and regions in the country and between classes and classes in the country.

Economic growth during the decade 1951-61 —I am referring to *per capita* income—was only 1.7 per cent. But in the second decade, that is, in the next decade, 1961-71, the rate of growth of *per capita* income declined to 0.8 per cent. The Jana Sangh Member very vehemently talked about problems of ecology. In the western countries today capitalist experts are talking about ecology. In fact, they are introducing an ecology scare and they are asking for a zero rate of growth. The Jana Sangh Member might be able to compliment Mr. Mohan Dharia and Mr. D. P. Dhar for enabling this country to have a zero rate of growth already. Where is the ecology scare necessary now? According to the western capitalist experts, Jana Sangh experts on the one hand and Mr. Mohan Dharia and Mr. D. P. Dhar on the other, between them, they have ensured that this country will have a zero rate of growth and therefore, the ecology problem is taken care of. In fact, to talk of ecology scare in a country which is backward, underdeveloped, agrarian, to talk about ecology in this country, is really to cut at the root of growth and development. What the people want is food; they want essential consumer goods. They are not at the moment going to be scared by the problems which the advanced capitalist countries of the West, the United States, Japan, Germany, etc. are today facing.

Sir, I come to my last point. How can these regional imbalances be remedied? We have one instrument of policy, namely, giving licences to industries. In the name of location principle, while giving licences to private industries, they are giving them to big capitalists without any reference to the problem of need for reducing imbalances. Public sector investments, even in the case of foot-loose industries which can be dispersed between region and region, are made in areas based on political haggling and political pressures exerted by the party people from various regions. It is not based on any principle or on the basis of the need for reducing regional imbalances. Even in regard to Central assistance and devolution of resources suggested by the Finance Commissions, the Government of India and the Planning Commission are pursuing a policy which is a money-lender's policy. A money-lender's policy is being pursued by the Planning Commission even with regard to devolution of resources and with regard to Central assistance.

I would like to know one thing from the hon. Minister, since he is here. The Sixth Finance Commission gave certain recommendations. Before that they repeatedly wanted the Planning Commission to have a dialogue with them. Shri D. P. Dhar the Deputy Chairman of the Planning Commission did not have the courtesy to meet the Sixth Finance Commission during the course of their work. The Deputy Chairman and the full Planning Commission did not have the courtesy to sit with the Sixth Finance Commission despite the fact that its Chairman wanted to have such a meeting. That shows they have no interest in co-ordinating the plan and non-plan finance and ensuring proper devolution in States so that grass-root planning is possible. By this way regional imbalances can be reduced.

In conclusion what is required is a complete restructuring of the power magnates in the country, a complete destruction of the power structure which is in the hands of monopoly capitalists, landlords, and imperialists. What is required is a change in the agricultural and industrial policies of the Government. What is required is a change in the green revolution policy which supports landlords. There should be a change in the policy of procurement which helps only Punjab, Haryana and a few landlords and traders. There is no need for any committee. If there is political will they can bring about these changes. Remedies and solutions to these problems have been suggested by a large number of expert bodies. If they have guts and courage they should come forward and bring about these changes. At least Shri Mohan Dharia, true to his conscience, should stand up and admit: "The policies which we have been following in the last 25 years are utterly wrong and we will change them in a direction which is true to the needs of this country and needs of democratic socialism".

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. V. RAJU): Since there is no change of this Resolution going beyond 5 P.M. today and since there is no other non-official day during this session, I think the House will be interested to have the views of the Government also. Otherwise there is no purpose. I, therefore, call upon Shri Dharia to speak for 10 minutes.

SHRI MOHAN DHARIA: Mr. Vice-Chairman, I am well aware that it is not possible for me to do justice within a span of 10 minutes. I would, however, touch some important points raised by the mover, Shri Shankar Lal Tiwari and other hon. Members. Sir, I would like to dispel some misapprehensions. During the past 25 years, it will be more appropriate to say that the gap between the rich and the poor both in rural areas and urban areas has widened. To say that the gap between the rural areas and urban areas has widened will not be correct in the sense that there are cities in this country which are highly populated, but without any industries. So, in such cities, where there is no industrialisation at all, you will find, Sir, that the cities have remained backward and they have remained poor also even though they are cities. Therefore, I would like to say that the gap between the rich and the poor has widened and the efforts that were made through our planned economy have not been able to achieve the desired results. Sir, my submission to this House is that it is true that the whole rural economy, as has been very rightly pointed out by Shri Shankarlal Tiwari, has been disrupted. Because of the modern concepts and because of industrialisation, the whole rural economy has been disrupted and we have to see how we can build up a new structure so that we can give additional employment or income to our

[Shri Mohan Dharia]

brothers and sisters in the rural areas and reasonable standards of living. So, Sir, it is in this context that I entirely agree with several Members here that, we would like to go ahead in a planned manner and industrialisation should not be concentrated and it will have to be necessarily decentralised. Now, Sir, I do not want to go into the way in which the arguments of Mr. Tiwari and Mr. Thengari were twisted by Dr. Kurian. But, Sir, if I have correctly understood Mr. Thengari, I think he wanted the new science and technology to be utilised for the rural industries, the age-old industries that exist in the country to day. Therefore, instead of mixing up these two arguments, I think it is better that we accept the argument made by Shri Thengari that it is very much necessary that our village industries, cottage industries, small-scale industries or, if I may use another word, the whole light industries in the country, should be assisted properly with the new science and technology. It is in this context the House will be happy to know that it was the first occasion for science and technology to be integrated the Fifth Plan was formulated, Sir, by the by, Dr. Kurian suggested that there was no liaison between the Sixth Finance Commission and the Planning Commission. But, Sir, let me tell this House that it was for the first time that a Member of the Sixth Finance Commission was also a Member of the Planning Commission.

DR. K. MATHEW KURIAN : He did not represent the views of the Planning Commission.

SHRI MOHAN DHARIA : I say with full authority that in order to have better co-ordination between the Sixth Finance Commission and the Planning Commission a Member of the Planning Commission. Dr. Minhas, was appointed on the Sixth Finance Commission.

DR. K. MATHEW KURIAN : The Planning Commission did not have any meeting despite repeated requestes by the Finance Commission.

SHRI MOHAN DHARIA : Dr. Minhas was able to convey our ideas, and he was the person who integrated the Sixth Finance Commission and the Planning Commission.

DR. K. MATHEW KURIAN : Dr. Minhas who differed with you?

SHRI MOHAN DHARIA : That is a different matter. On what points he has differed, the whole country knows and the House also knows. But there was integration and it was for the first time then that the Government took that care of having better co-ordination between the Planning Commission and the Sixth Finance Commission.

DR. K. MATHEW KURIAN : Sir, on a point of order. Either Mr. Dharia is not knowledgeable or he is deliberately misleading the House. I know it for certain—and I am prepared to prove it—that when the Sixth Finance Commission Chairman wrote to Mr. Dhar and even when they wrote the Report, they did not have the estimate of resources by the Planning Commission.

SHRI MOHAN DHARIA : I have said that there was proper co-ordination between these two Commissions. But it is true that there was no joint sitting of the Sixth Finance Commission and the Planning Commission on account of certain difficulties. But there were no differences or anything of that character.

Now, coming to the point, the House will kindly appreciate that there is no use of having any new committee of experts or a new committee of Members of Parliament. I do have all sympathies with the views expressed by hon. Members.

I would like to dispel one more fear here that those who are sitting at the helm of affairs are the persons coming from 'shehr' हमारे तिवारी साहब ने कहा कि जो नेता लोग हैं वे पूरे शहरी होते हैं, उन्हें ग्रामीण लोगों की मालूमात नहीं होतीं।

I would like to bring to the notice of Mr. Tewari that there are many sitting in the Government who come from rural areas. Even though I represent Poona City, I come from rural areas. I have spent twenty four years of my life in rural areas. I come from backward areas like Konkan. And naturally I am aware of the problems of rural areas... (*Interruptions*). Let there be no fear in the minds of hon. Ministers. We have taken care in the Fifth Plan to see how we can do justice to these rural areas. Sir, in this context, may I bring it to the notice of this House

that it was during the Fourth Five Year Plan, though not incorporated in the Fourth Plan, that various schemes were taken up—crash scheme for rural employment, marginal farmers' development agencies, agencies for agricultural labourers and small farmers. All such agencies were taken up. There were drought prevention programmes to the tune of hundred crores of rupees were taken up in the fourth plan. All possible efforts were made. But they are not enough. Therefore, in the Fifth Plan, not only we have encouraged all these programmes but we have gone a step further. In order to take better care of these rural areas, we have requested all State Governments to have sub-plans for tribal blocks that exist throughout the country. We have created special cells for hill areas. We have appointed a committee under the chairmanship of the Chief Minister of Maharashtra to take care of the western 'ghat' that runs through Maharashtra, Karnataka Goa, Kerala and Tamil Nadu. This is how we have decided to take steps to improve the condition in backward areas. It is in this Plan that we have taken up the minimum needs programme whereby certain basic minimum requirements of the common man—like schools, educational facilities health facilities, roads, drinking water facilities, nutrition, rural electrification, land sites for those who do not have an inch of land in the rural areas—are met with. Sir, here special funds are being allocated. Sir, we have requested the State Governments to earmark these funds for these special programmes and not to allow them to go from one sector to another sector, so that instead of depending upon contributions, it would be possible to render justice to the rural areas.

What is the main problem? The main problem is poverty. Why do people come from rural areas to the cities? Sir, to say that those who live in cities are enjoying a good life is not correct. I come from Poona City, where nearly one lakh and fifty thousand citizens live in slums. Similarly, in Bombay, nearly fifteen lakhs of people live in slums or on the footpaths. The life of those people who live in rural areas is much better...

DR. K. MATHEW KURIAN : The whole country is a slum.

SHRI MOHAN DHARIA : In spite of all the efforts of men like Dr. Kurian, who want to disrupt the economy of this country, we shall not allow this to happen... (*Interruptions*)

Dr. Kurian referred to party government. We are wedded to Democratic Socialism and my Party will take care to see that its economy is not disrupted. We can save this country... (*Interruptions*). Sir, the main problem is that it is the slum like mentality of men like Dr. Kurian, which is affecting the whole economy of the country.... (*Interruptions*).

DR. K. MATHEW KURIAN : They live in slums of black money.... (*Interruptions*).

SHRI MOHAN DHARIA : He always gets agitated because of his special love for me; I do not know.... (*Interruptions*). So, my submission is, why these people come from rural areas to cities? It is because of poverty, it is because of unemployment, it is because of under employment. And, therefore, we shall have to take care of the natural resources that exist in these local areas and see how the whole man-power could be well-harnessed so that they are gainfully employed and these resources are exploited fully, and see how the national inputs, credit facilities and the necessary managerial capacities are made available. These are the problems. It is in this context I would like to say-and many hon. Members have raised various questions and I have no time at my disposal to deal with them separately—that we have gone into all these matters at great length. I am not objecting to any committee. So far as committees and papers are concerned, I can assure the House that the Planning Commission is, perhaps, the biggest public sector undertaking in the country that produces committees, that produces papers in the country. I need not be sorry about this. But this matter would not be solved through committees. It requires a planned effort, and that care has been taken by the Government. I am grateful to the hon Members for their suggestions. I am sorry it was not possible for me to deal with several constructive ideas. But I can assure you that, as was rightly emphasised by Mr. Tiwari, it shall be our endeavour to take special care of those people who come from rural areas particularly the weaker sections in the country.

5 P.M.